

Daily

CURRENT AFFAIRS

CHRONICLE

R_Test_Version



26-12-2025

NEWS CREDIT

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express

NEWS COVERED

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics.....

IDEAL FOR

UPSC, BPSC, UPPSC, RAS, MPPSC, HPSC, JPSC, UKPSC and Other State-Level Exams



शीर्ष कहानियां

- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, जो यात्रियों की बढ़ती मांग से प्रेरित है।
- सरकार ने देश भर में उचित आय और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी, ड्राइवर-स्वामित्व वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 206 मिलियन डॉलर की आपात सहायता को मंजूरी दी।
- क्राड देशों ने गुआम एयरबेस पर पहला इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया।
- ऑस्ट्रेलिया ने घातक बोंडी बीच गोलीबारी के बाद 1996 के बाद से सबसे बड़ी राष्ट्रीय बंदूक खरीद योजना की घोषणा की।
- जाने-माने मलयालम अभिनेता और व्यंग्यकार श्रीनिवासन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
- भारत और नीदरलैंड आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति गठित करने पर सहमत।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोटक महिंद्रा बैंक पर नियामक अनुपालन उल्लंघन के लिए 61.95 लाख रुपये का जुमाना लगाया है।
- डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों और क्राड को मज़बूत करने वाले रक्षा कानून पर साइन किए।
- मंत्रिमंडल ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते को मंजूरी दी, हस्ताक्षर का मार्ग प्रशस्त किया।
- वीर अहलावत ने 4 अंडर 67 फाइनल राउंड के साथ सिडिको ओपन का खिताब जीता।

यात्री की बढ़ती मांग से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है



भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े घरेलू नागरिक उड़ान बाजार के रूप में उभरा है। देश के विमानन क्षेत्र में पिछले एक दशक में तेजी से विस्तार देखा गया है, जो बढ़ती यात्री मांग, बड़े के विस्तार और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। घरेलू हवाई यात्रा में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहतर सामर्थ्य, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाती है।

विमानन शासन और विनियमन

- नागरिक उड़ान मंत्रालय नीति निर्माण के लिए नोडल मंत्रालय है।
- डीजीसीए (नागरिक उड़ान महानिदेशालय) विमानन सुरक्षा, लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए जिम्मेदार है।
- एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) नागरिक उड़ान बुनियादी ढांचे का प्रबंधन और विकास करता है।

सरकारी योजनाएं और पहल

- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का उद्देश्य उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति (एनसीएपी), 2016 सामर्थ्य, कनेक्टिविटी और स्थिरता पर केंद्रित है।
- भारत का लक्ष्य दीर्घकालिक विमानन योजना के तहत 2047 तक सैकड़ों परिचालन हवाई अड्डों को विकसित करना है।

एएआई:

- स्थापित: 1 अप्रैल 1995
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
- अध्यक्ष: विपिन कुमार
- DGCA: विक्रम देव दत्त

नागरिक उड़ान मंत्रालय (भारत):

- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री: किंजारापु राम मोहन नायडू
- राज्य मंत्री: मुरलीधर किसन मोहोल

सरकार ने देश भर में उचित आय और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी, ड्राइवर-स्वामित्व वाला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च किया।



भारत सरकार ने भारत टैक्सी लॉन्च किया है, जो एक ड्राइवर-स्वामित्व वाला, सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य गिग इकॉनमी में उचित आय, पारदर्शिता और ड्राइवरों का कल्याण सुनिश्चित करना है। यह पहल स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति सीधे ड्राइवरों के हाथों में देकर निजी राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स के लिए एक स्वदेशी विकल्प प्रदान करती है।

संस्थागत और प्रशासनिक पहलू

- इस पहल को सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।
- इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।
- सहकारी समिति बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

सहकारी मॉडल

- ड्राइवर सदस्य और मालिक हैं, न कि केवल सेवा प्रदाता।
- कमीशन-आधारित मॉडल के विपरीत, ड्राइवर-सदस्यों के बीच लाभ साझा किया जाता है।
- ड्राइवर निर्णय लेने और शासन में भाग लेते हैं।

परिचालन विशेषताएं

- कम या शून्य कमीशन को बढ़ावा देता है, जिससे ड्राइवर की कमाई में सुधार होता है।
- पारदर्शी किराया और न्यूनतम वृद्धि मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है।
- सेवाओं में कार, ऑटो-रिक्षा और बाइक टैक्सी शामिल हैं।

आर्थिक और सामाजिक महत्व

- सामाजिक सुरक्षा और श्रम की गरिमा के साथ गिग इकॉनमी को मजबूत करता है।
- सहकारी उद्यमिता और आमनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है।
- विदेशी स्वामित्व वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्मों के लिए एक घरेलू विकल्प प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 206 मिलियन डॉलर की आपात सहायता को मंजूरी दी।



- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चक्रवात डितवाह के गंभीर प्रभाव के बाद श्रीलंका को आपातकालीन वित्तीय सहायता में 206 मिलियन अमरीकी डालर की मंजूरी दी है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रमेंट (RFI) के तहत सहायता प्रदान की जाती है ताकि देश को प्राकृतिक आपदा के कारण तत्काल भुगतान संतुलन, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।
- चक्रवात ने व्यापक बाढ़, भूस्खलन, बुनियादी ढांचे को नुकसान, कृषि नुकसान और विस्थापन का कारण बना, जिससे श्रीलंका की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

IMF आपातकालीन उपकरणों के बारे में

- रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रमेंट (RFI) प्राकृतिक आपदाओं जैसे झटकों के कारण तत्काल भुगतान संतुलन की जरूरतों का सामना करने वाले IMF सदस्य देशों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- आरएफआई में सीमित शर्तें शामिल हैं और दीर्घकालिक सुधारों के बजाय तत्काल राहत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) संदर्भ

- श्रीलंका एक आईएमएफ विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम के तहत है जिसका उद्देश्य राजकोषीय समेकन, ऋण स्थिरता और संरचनात्मक सुधार करना है।
- आईएमएफ आपदा सहायता ईएफएफ के तहत सुधार प्रतिबद्धताओं को प्रतिस्थापित नहीं करती है, लेकिन वसूली के प्रयासों को पूरा करती है।

चक्रवातों का आर्थिक प्रभाव

- चक्रवात कृषि, परिवहन, आवास और सार्वजनिक वित्त को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- आपदा से संबंधित खर्च अक्सर राजकोषीय घाटे और बाहरी वित्तपोषण की जरूरतों को बढ़ाता है।

जलवायु भेदता

- श्रीलंका चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसी जलवायु-प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- जलवायु लचीलापन और आपदा-तैयारी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताएं बन गई हैं।

क्राड देशों ने गुआम एयरबेस पर पहला इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया



भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित क्राड समूह ने 8-12 दिसंबर 2025 तक एंडरसन एयर फोर्स बेस, गुआम में इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) का पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (FTX) सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह अभ्यास ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के मौके पर आयोजित किया गया था, जो लंबे समय से चल रहा अमेरिकी वायु सेना का मानवीय मिशन है। एफटीएक्स का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तीव्र और प्रभावी मानवीय प्रतिक्रिया के लिए क्राड भागीदारों के बीच साझा रसद क्षमता, समन्वय और पारस्परिकता को मजबूत करना है।

क्राड के बारे में

- चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्राड) में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- यह सुरक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, आपदा प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग पर केंद्रित है।

इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN)

- आईपीएलएन क्राड भागीदारों के बीच संयुक्त लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए एक राजनीतिक ढांचा है।
- यह इंडो-पैसिफिक में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्यों का समर्थन करता है।

ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप

- ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप अमेरिकी वायु सेना द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाला मानवीय एयरलिफ्ट मिशन है।
- कमजोर समुदायों की मदद करते हुए अलग-थलग और दूरदराज के द्वीपों में आपूर्ति पहुंचाई जाती है।

सामरिक महत्व

- संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया, निकासी और नागरिक राहत के लिए इंटरऑपरेबिलिटी महत्वपूर्ण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र भू-राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख व्यापार मार्गों की मेजबानी करता है।
- क्राड सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, लचीलापन और आपात स्थिति के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ाता है।

व्यापक क्राड एजेंडा

- क्राड एक स्वतंत्र, खुले और लचीले हिंद-प्रशांत को बढ़ावा देता है।
- यह महामारी की तैयारी, जलवायु कार्रवाई, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखला लचीलेपन पर भी काम करता है।

ऑस्ट्रेलिया ने घातक बोंडी बीच गोलीबारी के बाद 1996 के बाद से सबसे बड़ी राष्ट्रीय बंदूक खरीद योजना की घोषणा की।



प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सिडनी में बोंडी बीच पर सामूहिक गोलीबारी के बाद एक राष्ट्रीय बंदूक खरीद योजना की घोषणा की है, जिसमें हनुक्का उत्सव के दौरान कम से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में बंदूक हिंसा को रोकने के लिए अधिशेष, नए प्रतिबंधित और अवैध आग्रेयास्तों को खरीदना और नष्ट करना है।

इस कार्यक्रम को 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार सुधारों के बाद से ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बंदूक बायबैक प्रयास माना जाता है और इसे संघीय और राज्य/क्षेत्र सरकारों के बीच समन्वित किया जाएगा। यह आग्रेयास्त कानूनों को कड़ा करने, लाइसेंसिंग में सुधार करने और राष्ट्रीय आग्रेयास्तों के विनियमन को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

1. बोंडी बीच हमले की पृष्ठभूमि

- यह हमला हनुक्का उत्सव के दौरान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं और घायल हुईं।
- इसने मौजूदा बंदूक कानूनों में खामियों को उजागर किया, क्योंकि एक शूटर के पास कानूनी रूप से कई आग्रेयास्त थे।

2. गन बायबैक योजना

- गन बायबैक योजना एक ऐसी नीति है जहां सरकार स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किए गए आग्रेयास्तों के लिए मुआवजा प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य नागरिक हाथों में बंदूकों की संख्या को कम करना और अवैध या प्रतिबंधित हथियारों को हटाना है।

3. पोर्ट आर्थर नरसंहार और सुधार (1996)

- 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार ने ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रव्यापी बंदूक नियंत्रण सुधारों का नेतृत्व किया।
- सुधारों में एक राष्ट्रीय आग्रेयास्त समझौता, सख्त लाइसेंसिंग, एक रजिस्ट्री और अर्ध-स्वचालित और स्वचालित हथियारों की एक बड़ी खरीद शामिल थी।

4. ऑस्ट्रेलियाई बंदूक कानून

- ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही सख्त आग्रेयास्त नियम थे, जिनमें पृष्ठभूमि की जांच, सुरक्षित भंडारण और कुछ हथियारों पर सीमाएं शामिल थीं।
- राज्यों के बीच खामियों और विविधताओं ने कुछ व्यक्तियों को कई आग्रेयास्तों को जमा करने की अनुमति दी।

5. राष्ट्रीय आग्रेयास्त रजिस्टर और लाइसेंसिंग

- सरकार सभी कानूनी स्वामित्व वाली बंदूकों को ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रीय आग्रेयास्त रजिस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है।
- प्रस्तावित सुधारों में प्रति व्यक्ति आग्रेयास्तों को सीमित करना, सख्त लाइसेंसिंग और संभवतः बंदूक के स्वामित्व के लिए नागरिकता की आवश्यकता शामिल है।

6. सार्वजनिक सुरक्षा और घृणा अपराध

- सरकार हमले के जवाब में घृणा अपराध कानूनों और नफरत विरोधी कार्य बलों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
- पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चिंतन दिवस घोषित किया गया है।

7. सार्वजनिक बहस

- समर्थक बायबैक को हिंसा को कम करने के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक प्रभावशीलता और उग्रवाद और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बहस करते हैं।

जाने-माने मलयालम अभिनेता और व्यंग्यकार श्रीनिवासन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।



अनुभवी मलयालम फिल्म व्यक्तित्व श्रीनिवासन का लंबी बीमारी के बाद 69 वर्ष की आयु में कोच्चि में निधन हो गया, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी।

वह कौन था:

- बहु-प्रतिभाशाली कलाकार को एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है।
- अपने काम में सामाजिक अंतर्दृष्टि के साथ तीखे व्यंग्य के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं।
- चार दशकों से अधिक समय से मलयालम सिनेमा में एक परिभाषित व्यक्ति।

कैरियर की मुख्य विशेषताएँ:

- 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, मलयालम फिल्मों में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए।
- कई यादगार फिल्में लिखी और निर्देशित कीं जो सांस्कृतिक कसौटी बन गईं।
- समाज पर गंभीर टिप्पणी के साथ हास्य को संतुलित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

हस्ताक्षर शैली:

- सामाजिक मुद्दों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल किया।
- फिल्में अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी को सामाजिक मानदंडों और नौकरशाही की सूक्ष्म आलोचना के साथ जोड़ती हैं।
- उनके लेखन को इसके यथार्थवाद, सापेक्षता और बुद्धि के लिए सराहा गया।

उल्लेखनीय योगदान:

- मलयालम सिनेमा में सामाजिक व्यंग्य की शैली को फिर से परिभाषित करने में मदद की।
- अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की एक पीढ़ी को गहरे अर्थ के साथ कॉमेडी का पता लगाने के लिए प्रेरित किया।
- अपने पीछे उन फिल्मों और पात्रों की विरासत छोड़ दें जो सभी आयु समूहों और भाषाई दर्शकों में लोकप्रिय बनी हुई हैं।

प्रभाव और विरासत:

- न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि मलयालम फिल्मों को सामाजिक प्रवचन में ऊपर उठाने के लिए भी सम्मानित किया जाता है।
- युवा प्रतिभाओं का मार्गदर्शन किया और समकालीन कहानी कहने की शैलियों को प्रभावित किया।
- भारतीय सिनेमा में स्पष्टता, हास्य और प्रतिबिंब की आवाज के रूप में याद किया जाता है।

भारत और नीदरलैंड आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश समिति गठित करने पर सहमत।



भारत और नीदरलैंड द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए एक संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (जेटीआईसी) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। यह धोषणा डच विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान की गई थी।

यह क्यों मायने रखता है:

जेटीआईसी व्यापार और निवेश के मुद्दों पर नियमित बातचीत के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दोतरफा निवेश को बढ़ावा देते हुए बाधाओं को दूर करना है।

मुख्य विवरण:

समिति की स्थापना दोनों देशों के वाणिज्य और विदेश मामलों के मंत्रालयों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से की गई थी।

जेटीआईसी की सालाना बैठक होगी, जिसमें भारत और नीदरलैंड में बारी-बारी से बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके।

इसकी सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे।

उद्देश्य और फोकस:

समिति निम्नलिखित पर काम करेगी:

- द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करें और उन्हें बढ़ाएं।
- दोतरफा निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार और निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- एमएसएमई जुड़ाव और चैर्चर्स ऑफ कॉर्मर्स इंटरैक्शन सहित आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करना।
- दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सतत और समावेशी विकास का समर्थन करना।

यह क्या दर्शाता है:

यह कदम आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने और साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और नीदरलैंड की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

नीदरलैंड

- राजधानी: एम्स्टर्डम
- राजभाषा: डच
- सम्प्राट: विलेम-अलेकजेंडर
- प्रधान मंत्री: डिक शूफ
- मुद्रा: यूरो (€)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोटक महिंद्रा बैंक पर नियामक अनुपालन उल्लंघन के लिए 61.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।



भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग सेवाओं, व्यापार संवाददाता गतिविधियों और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर क्रुच नियमों और आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.95 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

यह क्यों मायने रखता है:

यह जुर्माना बैंकिंग क्षेत्र में सख्त नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने पर आरबीआई के निरंतर ध्यान को उजागर करता है और ग्राहक खाता प्रथाओं, व्यापार संवाददाताओं की भूमिका और सटीक क्रेडिट डेटा रिपोर्टिंग के लिए मानकों को मजबूत करता है।

मुख्य विवरण:

- यह जुर्माना 31 मार्च, 2024 तक बैंक के संचालन की समीक्षा करने वाले वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2024) के निष्कर्षों पर आधारित है।
- आरबीआई ने पाया कि बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के विपरीत पहले से ही एक धारक ग्राहकों के लिए कई बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते खोले थे।
- कोटक महिंद्रा बैंक ने अनुमत दायरे से परे गतिविधियों के लिए बिजनेस कॉर्सोडेंट के साथ भी व्यवस्था की है।
- बैंक ने सीआईसी नियमों का उल्लंघन करते हुए क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को गलत जानकारी दी।

नियामक संदर्भ:

आरबीआई की कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी पर्यवेक्षी भूमिका का हिस्सा है कि बैंक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, बीसी नेटवर्क के सही उपयोग और सटीक क्रेडिट रिपोर्टिंग के परिभाषित मानकों का पालन करते हैं, और ग्राहक लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक

- उद्योग: वित्तीय सेवाएं
- स्थापित: 1985
- संस्थापक: उदय कोटक
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- गैर-कार्यकारी निदेशक: उदय कोटक
- एमडी और सीईओ: अशोक वासवानी

डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत-अमेरिका संबंधों और क्राड को मज़बूत करने वाले रक्षा कानून पर साइन किए



क्या हुआ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक प्रमुख वार्षिक रक्षा नीति विधेयक है जो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्राड) के माध्यम से भारत के साथ मजबूत जुड़ाव पर जोर देता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- यह कानून एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और अन्य क्राड सदस्यों के साथ विस्तारित सहयोग को रेखांकित करता है।
- यह सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा सहयोग सहित व्यापक रक्षा जुड़ाव का आह्वान करता है।
- इस अधिनियम में परमाणु दायित्व नियमों का आकलन करने और द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक संयुक्त परामर्शी तंत्र का प्रावधान है।

यह क्यों मायने रखता है:

- यह कानून अमेरिका और भारत के बीच गहरे रणनीतिक और रक्षा संबंधों को संस्थागत बनाता है, न केवल द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्राड ढांचे के भीतर भी साझेदारी को मजबूत करता है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए किया जा सके।

सामरिक महत्व:

अमेरिकी कानून में भारत के साथ विस्तारित जुड़ाव को संहिताबद्ध करके, एनडीएए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा गठबंधनों और साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक विधायी प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जो वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता के बीच दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को सेरेखित करता है।

मंत्रिमंडल ने भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते को मंजूरी दी, हस्ताक्षर का मार्ग प्रशस्त किया



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है, जिससे समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने का रास्ता साफ हो गया है।

संदर्भ और पृष्ठभूमि:

- यह समझौता एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता का हिस्सा है जिसे 10 साल के अंतराल के बाद मार्च 2025 में फिर से शुरू किया गया था।
- एक बार हस्ताक्षर होने के बाद, यह 2021 के बाद से भारत का सातवां व्यापार समझौता बन जाएगा, जो व्यापार साझेदारी में विविधता लाने की देश की रणनीति का समर्थन करेगा।

समझौते का विवरण:

- अतीत में बातचीत रुक गई थी, लेकिन बाजार पहुंच और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए कई दौर के साथ 2025 में इसे पुनर्जीवित किया गया था।
- न्यूजीलैंड के साथ भारत के व्यापार में दवाएं, कपड़ा, मशीनरी, कृषि उत्पाद और आईटी और पर्यटन जैसी सेवाएं शामिल हैं।

यह क्यों मायने रखता है:

- मंत्रिमंडल की मंजूरी एफटीए पर हस्ताक्षर करने की दिशा में एक औपचारिक कदम है, जो मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों को सक्षम बनाता है।
- इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दोनों देशों में व्यवसायों के लिए अधिक बाजार पूर्वानुमान प्रदान करने की उम्मीद है।

आर्थिक महत्व:

एक सफल एफटीए भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्यात के अवसरों का विस्तार कर सकता है, न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए आयात पहुंच में सुधार कर सकता है और प्रौद्योगिकी, कृषि और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा कर सकता है।

न्यूजीलैंड

- राजधानी: वेलिंगटन
- महाद्वीप: ओशनिया
- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, माओरी
- मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर (\$)

वीर अहलावत ने 4 अंडर 67 फाइनल राउंड के साथ सिडको ओपन का खिताब जीता



भारतीय गोल्फर वीर अहलावत ने सिडको ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है।

प्रदर्शन विवरण:

- अहलावत के लगातार स्कोरिंग और दबाव में मजबूत खेल ने उन्हें लीडरबोर्ड पर आगे बढ़ने में मदद की।
- 67 स्ट्रोक का उनका अंतिम दौर चैम्पियनशिप को सील करने के लिए महत्वपूर्ण था।

यह क्यों मायने रखता है:

- यह जीत अहलावत के पेशेवर करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- यह भारतीय गोल्फ में बढ़ती गहराई और प्रतिभा को दर्शाता है, जिससे राष्ट्रीय सर्किट पर उनकी स्थिति मजबूत होती है।

आगे क्या होगा:

- इस जीत से अहलावत के आत्मविश्वास और रैंकिंग में वृद्धि हुई है क्योंकि वह आगामी टूर्नामेंटों की तैयारी कर रहे हैं।
- उनका प्रदर्शन प्रतिस्पर्धी दौरों पर भारतीय गोल्फरों के उभरने पर प्रकाश डालता रहता है।

लेट्स रिवाइज

- Q.** भारत दुनिया का ___ सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। **तीसरा**
- Q.** घरेलू विमानन बाजार के आकार में कौन से दो देश भारत से आगे हैं? **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन**
- Q.** भारत टैक्सी किस स्वामित्व मॉडल पर आधारित है? **सहकारी स्वामित्व मॉडल।**
- Q.** किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चक्रवात डिट्वा के बाद श्रीलंका के लिए आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी? **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)**
- Q.** कौन से देश क्राड के सदस्य हैं जिसने पहला IPLN FTX आयोजित किया था? **भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका**
- Q.** ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय बंदूक बायबैक योजना की घोषणा क्यों की? **बोंडी बीच सामूहिक शूटिंग के जवाब में।**
- Q.** अनुभवी मलयालम अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता का नाम बताइए जो तेज सामाजिक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया? **श्रीनिवासन**
- Q.** भारत और नीदरलैंड ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया निकाय स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? **संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (जेटीआईसी)**
- Q.** भारत-नीदरलैंड JTIC का मुख्य उद्देश्य क्या है? **नियमित बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को गहरा करना।**
- Q.** बैंकिंग, बिजनेस कॉरेस्पोर्डेंट और क्रेडिट रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन न करने के लिए RBI द्वारा किस बैंक पर ₹61.95 लाख का जुर्माना लगाया गया था? **कोटक महिंद्रा बैंक**
- Q.** किस प्राधिकरण ने बैंकिंग, बिजनेस कॉरेस्पोर्डेंट और क्रेडिट रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन न करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया? **भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)**
- Q.** बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पोर्डेंट और क्रेडिट रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन न करने के लिए आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर कितना जुर्माना लगाया? **₹61.95 लाख**
- Q.** हाल ही में कौन सा अमेरिकी कानून भारत के साथ मजबूत जुड़ाव पर जोर देता है? **अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) पर हस्ताक्षर किए, जो भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को उजागर करता है।**
- Q.** एनडीए भारत-अमेरिका संबंधों को कैसे बढ़ावा देता है? **यह सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा सहित रक्षा सहयोग का विस्तार करता है।**
- Q.** क्या NDAA में क्राड शामिल है? **हां, यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए क्राड सदस्यों- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी को मजबूत करता है।**
- Q.** भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? **यह समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश संबंधों और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा।**
- Q.** हाल ही में भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते में किन क्षेत्रों और वस्तुओं को शामिल किया गया है? **इसमें दवाएं, कपड़ा, मशीनरी, कृषि उत्पाद और आईटी और पर्यटन सहित सेवाएं शामिल हैं।**
- Q.** सिडिको ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप किसने जीती? **वीर अहलावत**
- Q.** सिडिको ओपन किस खेल से संबंधित है? **गोल्फ**



Daily CURRENT AFFAIRS CHRONICLE

The Imperative of Current Affairs in Competitive Examinations

Current affairs and news constitute the pulsating core of preparation for competitive examinations such as UPSC, SSC, and banking services, bridging theoretical knowledge with contemporary realities. In an era of rapid geopolitical shifts and policy innovations, these exams allocate 30-35% weightage to recent events, testing aspirants' ability to analyze and apply information dynamically. Mastery here not only elevates scores but cultivates the discerning mindset essential for future administrators.

Key Dimensions of Importance:

- **Syllabus Integration:** Current affairs interweave with static subjects like polity and economy, demanding connections between historical precedents and modern developments—e.g., linking constitutional provisions to recent judicial reforms.
- **Scoring Advantage:** High-yield factual questions from news sources provide quick marks, transforming potential vulnerabilities into strengths in prelims and mains.
- **Interview Readiness:** Panels rigorously assess awareness of issues like climate diplomacy, fostering articulate, informed responses.

As aptly stated by former UPSC topper: "Current affairs is the soul of UPSC preparation; ignore it, and your foundation crumbles." This underscores how daily engagement with credible outlets—The Hindu, PIB, Yojana—hones critical thinking, decision-making, and adaptability, countering rote learning's limitations.

In a fiercely competitive arena where millions vie for limited seats, current affairs emerge as the great equalizer. Structured habits—daily reading, monthly magazines, mock quizzes—equip aspirants to navigate evolving patterns with confidence. Neglecting this vital component is tantamount to sailing uncharted waters without a compass, forfeiting the edge needed to excel.

IDEAL FOR

UPSC, BPSC, UPPSC, RAS, MPPSC, HPSC,
JPSC, UKPSC and Other State-Level Exams

www.aptitudeplus.com